RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
जुलाई
19
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

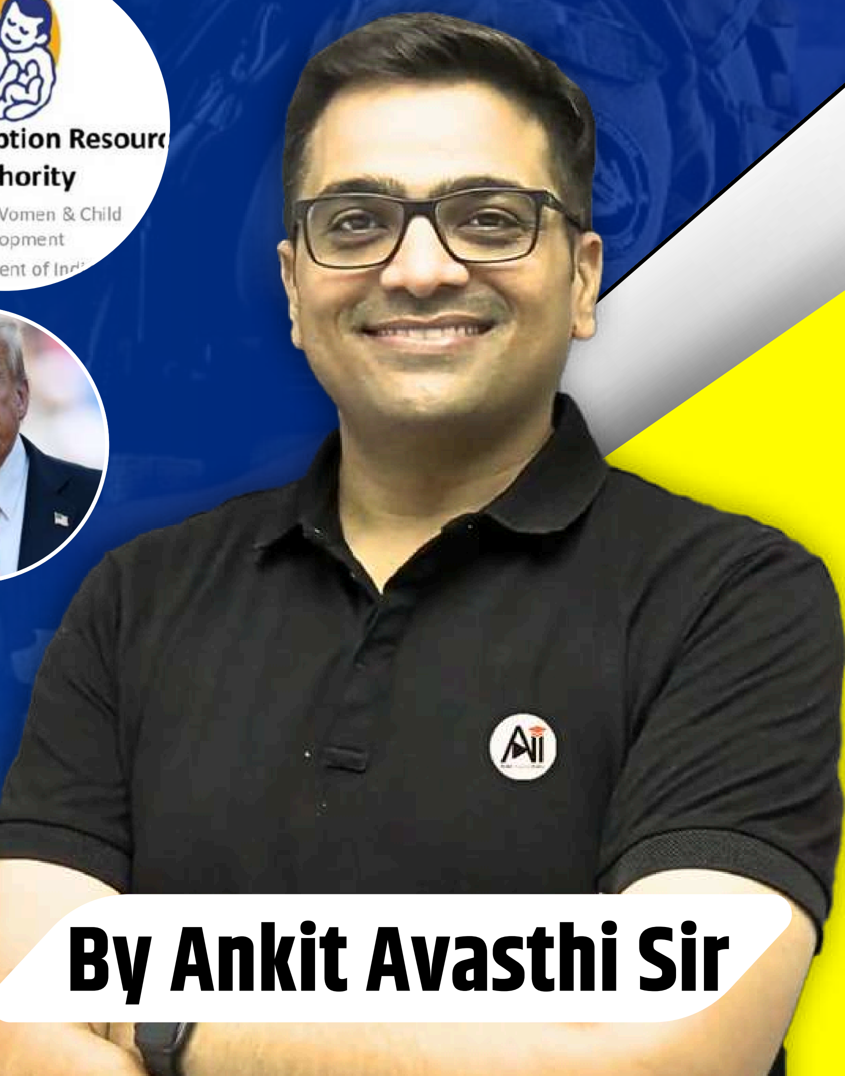

By Ankit Avasthi Sir

रूसी तेल: भारत ने 'दोहरे मापदंड' की निंदा की / Russian Oil: India calls out 'double standards'

संदर्भ:

भारत ने अमेरिका में पेश किए गए **Russian Sanctions Act 2025** पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) पर **500% तक शुल्क** लगाने का प्रस्ताव है। भारत ने इस विधेयक को लेकर वैश्विक कूटनीति में **"दोहरे मापदंडों"** के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि यह विकासशील देशों की **ऊर्जा संप्रभुता** को कमजोर करने वाला कदम है।

भारत ने US-Russia Sanctions Act, 2025 का विरोध क्यों किया है?

भारत ने प्रस्तावित **US-Russia Sanctions Act, 2025** का विरोध स्पष्ट रूप से इन प्रमुख कारणों से किया है:

ऊर्जा सुरक्षा:

- भारत रूस से रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, जिससे घरेलू ईंधन मूल्य नियंत्रण में रहता है।
- यह विधेयक भारत की सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल सकता है, जो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है।

रणनीतिक स्वायत्तता:

- भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और किसी भी बाहरी दबाव का विरोध करता है।
- यह विधेयक भारत को उसकी संप्रभु निर्णय प्रक्रिया से पीछे हटने को मजबूर करने का प्रयास प्रतीत होता है।

चयनात्मक प्रतिबंधों का विरोध:

- भारत ने अमेरिका पर **'भू-राजनीतिक दोहरे मानकों'** का आरोप लगाया है।
- जहां भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर दबाव है, वहीं कई यूरोपीय देश आज भी रूस से प्राकृतिक गैस खरीद रहे हैं, उन्हें ऐसी कोई सजा नहीं दी जा रही।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात पर US Sanctions Act, 2025 के संभावित प्रभाव

तेल आपूर्ति में बाधा:

- यह अधिनियम भारतीय कंपनियों को रूसी ऊर्जा फर्मों से व्यापार करने से रोक सकता है।
- Indian Oil Corporation जैसी कंपनियों को Rosneft से दीर्घकालिक अनुबंध जारी रखने में कठिनाई हो सकती है।

ऊर्जा लागत में वृद्धि: रियायती रूसी तेल तक सीमित पहुंच से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है और घरेलू ईंधन की कीमतों में उछाल आ सकता है।

आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता: यह अधिनियम भू-राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है, जिससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर हो सकती है।

भारत के कच्चे तेल आयात की स्थिति: प्रमुख तथ्य

विश्व में स्थान: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है।

आयात पर निर्भरता: भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 88% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद बदलाव: 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद, भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद में तेज़ी लाई।

मुख्य आयात स्रोत देश: भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता देश हैं: इराक, सऊदी अरब, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.), संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

भारत द्वारा कच्चे तेल आयात प्रबंधन के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण: भारत विभिन्न देशों जैसे इराक, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो।

स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPR): आपातकाल या भू-राजनीतिक संकट की स्थिति में आपूर्ति बनाए रखने हेतु भारत ने रणनीतिक तेल भंडार विकसित किए हैं।

घरेलू उत्पादन को बढ़ावा: Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) जैसी पहलों के माध्यम से भारत घरेलू तेल खोज और उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े।

ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक स्रोत: भारत नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कच्चे तेल पर समग्र निर्भरता घटे।

द्विपक्षीय समझौते: भारत ने सऊदी अरब, इराक और रूस जैसे देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं ताकि स्थिर और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

J&K पुलिस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ सटीक और सशक्त कार्रवाई / Precise and strong action against terrorism led by J&K police

संदर्भ:

जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का सफाया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है — यह बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी, उधमपुर में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा बलों की वीरता और जनता के सहयोग से जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता कायम की जा रही है। उन्होंने पारंपरिक बीट पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक, खुफिया जानकारी, सामुदायिक भागीदारी और एजेंसी समन्वय के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में स्थानीय पुलिस की केंद्रीय भूमिका

उपराज्यपाल का जोर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकवाद से लड़ने में जम्मू-कश्मीर पुलिस (JAKP) की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया है।

स्थानीय पुलिस की रीढ़ की भूमिका: यह तथ्य स्थापित है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों की रीढ़ स्थानीय पुलिस होती है; केंद्रीय बल केवल सहायक भूमिका निभा सकते हैं।

JAKP की विशिष्ट ताकतें:

- क्षेत्र की भूगोल, जनसांख्यिकी और सामुदायिक नेटवर्क की गहरी समझ।
- इससे मानव-खुफिया (HUMINT) संग्रह बेहतर होता है।

स्थानीय खुफिया तंत्र की कमी का उदाहरण: 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में हमलावर अब तक पकड़े नहीं गए हैं — यह स्थानीय खुफिया में कमी को दर्शाता है।

सुधार की आवश्यकता: ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए JAKP में लगातार कार्यात्मक सुधार ज़रूरी है।

स्थानीय प्रतिनिधियों की अहम भूमिका:

- सरपंचों और विधायकों के पास स्थानीय लोगों का विश्वास और कई बार आतंकी गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है।
- इन्हें सुरक्षा ढांचे में शामिल करना दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में स्थानीय पुलिस और जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका

स्थानीय ज़मीनी जानकारी की ताकत:

- जम्मू-कश्मीर पुलिस (JAKP) को इलाके की भूगोल, बोली और सामाजिक संरचना की गहरी समझ होती है।

सामुदायिक जुड़ाव और विश्वास: स्थानीय पुलिस और जनता के बीच बना विश्वास आतंकियों के खिलाफ समय पर मानव खुफिया (HUMINT) जुटाने में सहायक होता है।

प्रशिक्षित और अनुभवी बल: JAKP को दशकों का अनुभव है — खुफिया एकत्रीकरण, तलाशी अभियान और कट्टरता रोकने में।

जम्मू-कश्मीर में समावेशी सुरक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाना आवश्यक

सुरक्षा तंत्र से बाहर रखने का दुष्परिणाम: निर्वाचित प्रतिनिधियों को सुरक्षा ढांचे से अलग रखना न केवल सुशासन को कमजोर करता है, बल्कि आतंकवाद-रोधी प्रयासों को भी प्रभावित करता है।

JAKP को चुनी हुई सरकार के अधीन लाना जरूरी: इससे पुलिसिंग में जवाबदेही बढ़ेगी और नीतियां जनता की ज़मीनी ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करेंगी।

पुलिस और जनता के बीच पुल की भूमिका: विधायक, सरपंच जैसे नेता पुलिस व नागरिकों के बीच विश्वास का पुल बनते हैं, जो प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है।

सिर्फ चुनाव नहीं, वास्तविक भागीदारी चाहिए: विधानसभा और लोकसभा चुनाव केवल लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति हैं, लेकिन वास्तविक भागीदारी तब होगी जब इन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा नीति में भी शामिल किया जाएगा।

ऊपर-से-नीचे मॉडल से आगे बढ़ने की जरूरत: जब तक नीति-निर्माण में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका नहीं बढ़ेगी, तब तक समुदाय-आधारित सुरक्षा दृष्टिकोण अधूरा रहेगा।

स्थानीय लोकतंत्र को सशक्त करना ही समाधान: स्थानीय भागीदारी को मज़बूत करना जम्मू-कश्मीर में बेहतर शासन और सुरक्षा स्थिति सुधारने की कुंजी है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

- **अनुच्छेद 370 हटाना:** 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर पूरे भारत के साथ एकीकरण और समान कानून लागू किए गए।
- **सुरक्षा व्यवस्था मजबूत:** आतंकवाद पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती, निगरानी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया।
- **विकास पहल:** पीएमडीपी और 'बैक टू विलेज' जैसी योजनाएं शुरू की गईं ताकि शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिल सके।

चीन की हरित ऊर्जा नीति / Green energy policy of China

संदर्भ:

हाल ही में चीन ने वैश्विक हरित ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश कर और नेतृत्व संभाल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। पर्यावरणीय संकट और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चीन ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अपने निवेश को तेजी से बढ़ाया है, जिससे वह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है।

चीन की हरित ऊर्जा नीति के रणनीतिक आधार

नीतियों और निवेश के ज़रिए सुनियोजित बदलाव:

- चीन की हरित ऊर्जा की यात्रा 2000 के दशक की शुरुआत में छोटे-छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स से शुरू हुई।
- 2005 का Renewable Energy Law और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2006–2010) ने स्वच्छ ऊर्जा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया।
- सरकार ने सब्सिडी, ग्रिड एक्सेस गारंटी और रेगुलेटरी प्रोत्साहन जैसे उपायों से हरित उत्पादकों को बढ़ावा दिया।

वित्तीय निवेश में असाधारण वृद्धि:

- चीन का निवेश 2006 में $10.7 बिलियन से बढ़कर 2024 में $940 बिलियन तक पहुंच गया (स्रोत: Carbon Brief)।
- तुलना में भारत ने 2024–25 में केवल $3.4 बिलियन आकर्षित किए, जो चीन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रदूषण और ऊर्जा असुरक्षा से निपटना:

- बीजिंग और शंघाई में वायु प्रदूषण संकट के स्तर पर पहुंच गया, जिससे जनता में रोष और सरकार की तत्काल कार्रवाई शुरू हुई।
- साथ ही, तेजी से बढ़ती बिजली मांग और तेल आयात पर निर्भरता के कारण चीन ने ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण शुरू किया।

चीन की हरित रणनीति को प्रेरित करने वाले घरेलू कारण

गंभीर वायु प्रदूषण:

- विशेष रूप से *बीजिंग* जैसी औद्योगिक शहरों में *विषैली हवा* ने *जनस्वास्थ्य संकट* और *सामाजिक असंतोष* को जन्म दिया।
- इससे सरकार को *कड़े पर्यावरणीय सुधार* लागू करने पड़े।

ऊर्जा असुरक्षा:

- चीन की अर्थव्यवस्था *कोयले और आयातित तेल* पर अत्यधिक निर्भर थी, जिससे *ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों में अस्थिरता* बनी रही।
- इसे कम करने के लिए चीन ने *सौर और पवन ऊर्जा* का तेज़ी से विस्तार किया, जिससे *ऊर्जा आत्मनिर्भरता* बढ़े।

आर्थिक संतुलन की आवश्यकता:

- चीन को भारी उद्योग-आधारित अर्थव्यवस्था से नवाचार-आधारित विकास और हरित नौकरियों की ओर बढ़ने की ज़रूरत थी।
- 13वीं और 14वीं पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सरकार ने हरित उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे सतत विकास और प्रौद्योगिकी नेतृत्व सुनिश्चित हो सके।

चीन की हरित ऊर्जा नीति: चुनौतियाँ और सुधारात्मक कदम

बुनियादी ढांचे की बाधाएँ:

- पवन और सौर ऊर्जा का तेज़ विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि पावर ग्रिड उसके अनुरूप तैयार नहीं था।
- परिणामस्वरूप, इनर मंगोलिया और गांसू जैसे प्रांतों में 20% तक ऊर्जा कटौती (curtailment) देखी गई।
- समाधान के रूप में चीन ने अल्ट्रा-हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में भारी निवेश किया और State Grid का दशक भर में निवेश दोगुना कर दिया।

सब्सिडी-आधारित अक्षमताएँ:

- प्रारंभिक चरण में सरकारी सब्सिडी ने अति-निर्माण और दक्षता की कमी को बढ़ावा दिया।
- इसके जवाब में बीजिंग ने नियामक निगरानी को सख्त किया और ग्रिड-तैयारी को प्राथमिकता देते हुए दक्षता-आधारित योजना को बढ़ावा दिया।

भारत सरकार द्वारा हरित ऊर्जा क्षेत्र में उठाए गए प्रमुख कदम

राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission):

- *राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)* के तहत शुरू किया गया।
- उद्देश्य: *2030 तक 280 GW* सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य।
- *2024 तक भारत ने 81 GW* सौर क्षमता पार कर ली है।

हरित हाइड्रोजन मिशन :

- *राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन* के तहत भारत को *ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र* बनाने का लक्ष्य।
- इसका उपयोग परिवहन, उर्वरक, और भारी उद्योगों को कार्बन-मुक्त करने में किया जाएगा।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण / Central Adoption Resource Authority (CARA)

संदर्भ:

केंद्रीय गोद लेना संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने हाल ही में सभी राज्य गोद लेना संसाधन एजेंसियों (SARAs) को नए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश **जुवेनाइल जस्टिस (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** (2021 में संशोधित) की **धारा 70(1)(a)** के तहत प्रदत्त अधिकारों और **गोद लेने के विनियम, 2022** के अनुसार जारी किए गए हैं।

SARAs को दिए गए प्रमुख निर्देश:

- **साइकोसोशल सहयोग को सुदृढ़ बनाना:** प्रत्येक संबंधित पक्ष जैसे—**गोद लेने वाले संभावित माता-पिता (PAPs), दत्तक बच्चे**, तथा **जैविक माता-पिता**—के लिए साइकोसोशल सहायता ढांचे को मजबूत करने का निर्देश।
- **काउंसलरों की नियुक्ति/पैनल में शामिल करना:** राज्य और जिला स्तर पर योग्य काउंसलरों को नामित या पैनल में शामिल करने का निर्देश।
- **अन्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप:** यदि आवश्यकता समझी जाए, तो विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों (SAAs) या जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPUs) के आकलन के आधार पर अन्य किसी भी परिस्थिति में साइकोसोशल हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए।

भारत में दत्तक ग्रहण (Adoption in India): प्रमुख प्रावधान

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA):

- लागू होता है: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मावलंबियों पर।
- न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं।
- व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित, लेकिन HAMA के तहत कुछ विशेष शर्तों का पालन अनिवार्य होता है।

किशोर न्याय (बालों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act):

- लागू होता है: सभी भारतीय नागरिकों पर, धर्म की परवाह किए बिना।
- दत्तक ग्रहण केवल अदालत के आदेश से होता है।
- प्रशासन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत CARA (Central Adoption Resource Authority) द्वारा किया जाता है।

CARA (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण): एक वैधानिक निकाय, जो अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण की मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से निगरानी और नियमन करता है।

CARA (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण): प्रमुख तथ्य

स्थापना व प्रशासन: एक *वैधानिक निकाय* है जो *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय* के अंतर्गत कार्य करता है।

प्रमुख कार्य: *घरेलू (In-country)* और *अंतरराष्ट्रीय (Inter-country)* दत्तक ग्रहण की निगरानी और नियमन।

- *मान्यता प्राप्त एजेंसियों* के माध्यम से दत्तक प्रक्रिया का संचालन।

अंतरराष्ट्रीय मान्यता: Hague Convention on Inter-country Adoption, 1993 के तहत भारत की केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित (भारत ने 2003 में इसका अनुमोदन किया)।

- अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

उद्देश्य: अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों का सुरक्षित, नैतिक और कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण सुनिश्चित करना।

CARA के अंतर्गत दत्तक ग्रहण: प्रमुख दिशा-निर्देश

बच्चों के लिए पात्रता:

- बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया गया हो।
- 18 वर्ष से कम आयु के हों।
- अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पित बच्चे हों।

दत्तक माता-पिता की पात्रता (JJ अधिनियम के तहत):

- कोई भी भारतीय नागरिक (NRI, OCI कार्डधारक सहित)।
- विवाहित जोड़े: कम से कम 2 वर्षों का स्थिर विवाह संबंध अनिवार्य।
- अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा/विधुर व्यक्ति भी पात्र।
- दत्तक माता-पिता और बच्चे के बीच न्यूनतम 25 वर्ष का आयु अंतर अनिवार्य।

इस्वातिनी / Eswatini

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए **पांच विदेशी नागरिकों** को **एस्वातिनी** वापस भेज दिया है। यह कार्रवाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अपराध और अवैध आव्रजन पर सख्ती से निपटने की नीति के तहत की गई है।

इस्वातिनी (Eswatini): प्रमुख तथ्य

भौगोलिक स्थिति:

- दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध (landlocked) देश।
- दक्षिण अफ्रीका और मोज़ाम्बिक से इसकी सीमा लगती है।

आर्थिक संबंध:

- कॉमन मोनेटरी एरिया (CMA) का सदस्य है, जिसमें लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

ऐतिहासिक नाम परिवर्तन:

- पहले इसका नाम स्वाज़ीलैंड (Swaziland) था।
- 2018 में इसका नाम बदलकर इस्वातिनी रखा गया, जिससे पूर्व-औपनिवेशिक पहचान को दर्शाया गया।

राजनीतिक व्यवस्था:

- अफ्रीका का एकमात्र देश जो पूर्ण राजशाही (absolute monarchy) के तहत शासित है।
- राजा मस्वाती III 1986 से शासन कर रहे हैं और सरकार की सभी शक्तियाँ उनके पास केंद्रित हैं।
- राजा डिक्री (decree) के माध्यम से शासन करते हैं।

सामाजिक व आर्थिक चुनौतियाँ:

- आबादी का आधे से अधिक हिस्सा प्रतिदिन $4 से कम पर जीवन यापन करता है।
- एचआईवी संक्रमण दर लगभग 26% के साथ विश्व में सर्वाधिक है।

क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी / CVI

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुरानी शिरापरक अपर्याप्तता (Chronic Venous Insufficiency - CVI) का निदान व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में पैरों में सूजन और हाथों में चोट के निशानों की जांच के बाद Chronic Venous Insufficiency से पीड़ित पाया गया है।

Chronic Venous Insufficiency (CVI): प्रमुख तथ्य

परिभाषा:

- Chronic Venous Insufficiency (CVI) एक प्रकार का शिरा विकार (vein disorder) है, जो तब होता है जब पैरों की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

कारण:

- सामान्यत: नसों में वाल्व (valves) होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर ऊपर की दिशा में प्रवाहित करने में मदद करते हैं।
- जब ये वाल्व सही से बंद नहीं होते, तो रक्त नीचे की ओर वापस बहता है – इसे Venous Reflux कहते हैं।

परिणाम:

- इससे रक्त पैरों के निचले हिस्से (विशेषकर टखनों और पैरों) में जमा होने लगता है, जिससे सूजन और अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं।

लक्षण:

- सूजन (मुख्यत: टखनों के चारों ओर)
- पैरों में दर्द या थकान,
- भारीपन या झुनझुनी की अनुभूति,
- वेरिकोज वेन्स (Varicose Veins) का उभर आना।

जोखिम:

- लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना
- अधिक उम्र, मोटापा, गर्भावस्था
- पूर्व में गहरी शिरा घनास्रता (Deep Vein Thrombosis – DVT) का इतिहास

उपचार:

- कंप्रेशन स्टॉकिंग्स (compression stockings) का उपयोग
- व्यायाम, पैर ऊपर उठाकर रखना
- गंभीर मामलों में लेजर या सर्जिकल हस्तक्षेप

द रेजिस्टेंस फ्रंट / TRF

संदर्भ:
दक्षिण एशिया में उभरते आतंकी नेटवर्कों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता के बीच, अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 'द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)' को **विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO)** और **विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT)** घोषित किया है। यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की सख्त नीति को दर्शाता है।

The Resistance Front (TRF): प्रमुख तथ्य

स्थापना:
- TRF की स्थापना 2019 में की गई थी, और यह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का प्रॉक्सी संगठन है।

प्रतिबंध:
- भारत सरकार ने 2023 में TRF को गैरकानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया।

मुख्य गतिविधियाँ:
- ऑनलाइन युवाओं की भर्ती
- आतंकियों की घुसपैठ में सहायता
- हथियार व मादक पदार्थों की तस्करी पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में
- नागरिकों, राजनेताओं और सुरक्षा बलों पर हमलों की जिम्मेदारी लेना

प्रमुख हमले: 22 अप्रैल 2025 को बायसरण घाटी (जिसे 'मिनी स्विट्ज़रलैंड' कहा जाता है) में नागरिकों पर आतंकी हमला – 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया।

नेतृत्व: संस्थापक व कमांडर: शेख सज्जाद गुल, जिन्हें UAPA (1967) के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।

पाकिस्तान का समर्थन: TRF को पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है।
- ISI इस संगठन का इस्तेमाल कश्मीर क्षेत्र को अस्थिर बनाए रखने की रणनीति के तहत करता है।

खसरा / Measles

संदर्भ:
भारत ने **बोलीविया में फैले बड़े खसरा प्रकोप** के जवाब में **3 लाख खसरा-रूबेला (Measles-Rubella) वैक्सीन डोज़** भेजी हैं। यह मानवीय सहायता भारत के वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग और 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना को दर्शाती है।

खसरा (Measles): प्रमुख तथ्य

रोग का प्रकार:
- यह *वायुवाहित (airborne)* और *अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग* है।
- यह *Paramyxovirus* परिवार के वायरस के कारण होता है।

संक्रमण का तरीका:
- *खांसी, छींक* या *प्रत्यक्ष संपर्क* से *श्वसन बूंदों (respiratory droplets)* के माध्यम से फैलता है।
- वायरस सबसे पहले *श्वसन तंत्र* को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है।

जटिलताएं (Complications):
- संक्रमण के बाद *निमोनिया, डायरिया, अंधापन,* और *मस्तिष्क में सूजन* जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
- *मृत्यु* की संभावना भी बनी रहती है, विशेषकर कुपोषित बच्चों में।

उपचार:
- *कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं* है।
- इलाज *लक्षणों के आधार पर* किया जाता है।

रोकथाम: *खसरा-रूबेला (Measles-Rubella: MR)* टीका मुख्य रोकथाम उपाय है।
- आमतौर पर *दो खुराकें* दी जाती हैं– *9 माह* और *16-24 माह* की उम्र में।

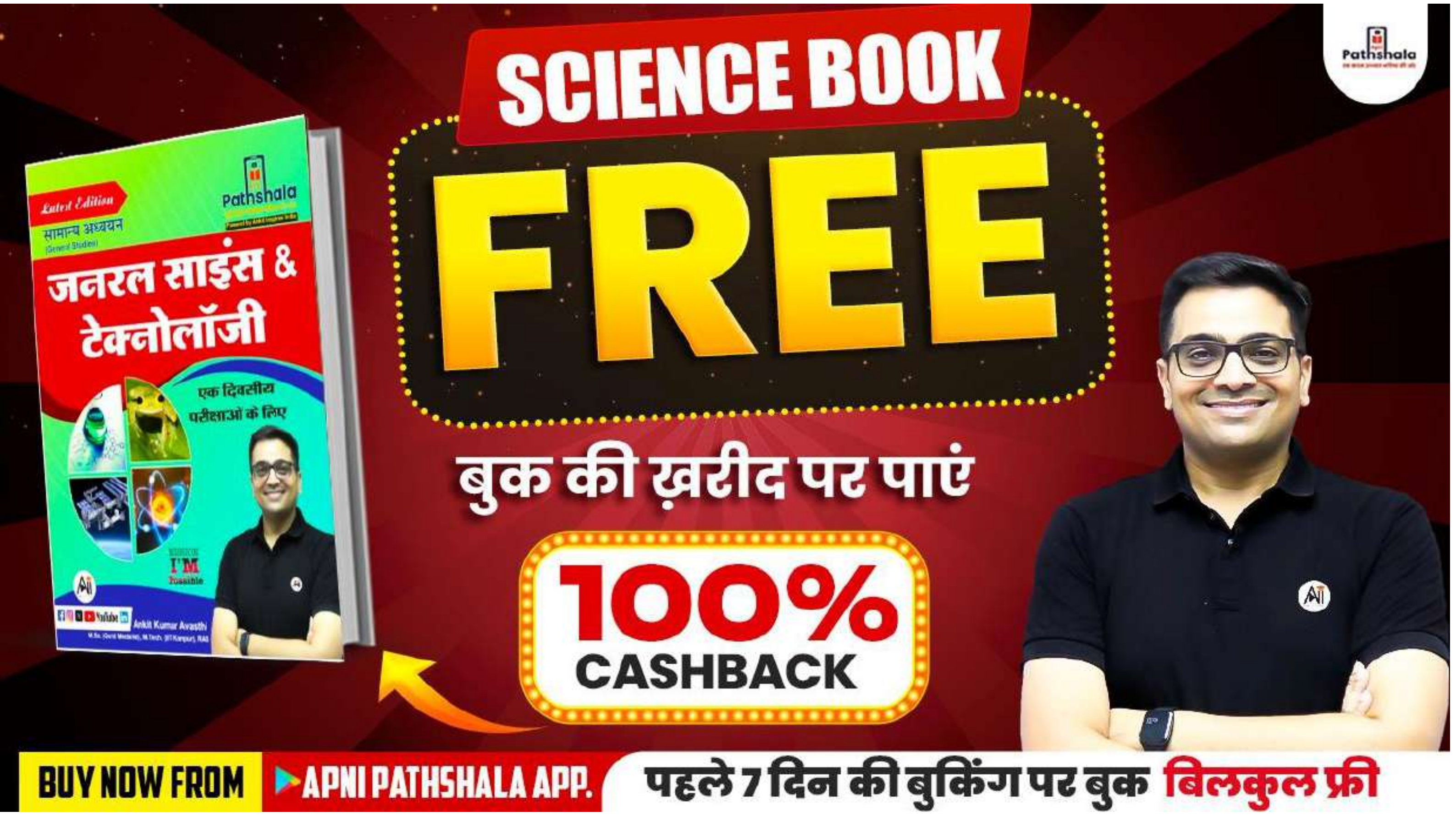
SCIENCE BOOK
FREE
बुक की ख़रीद पर पाएं
100%
CASHBACK
Pathshala
Latest Edition
सामान्य अध्ययन
(General Studies)
जनरल साइंस &
टेक्नोलॉजी
एक दिवसीय
परीक्षाओं के लिए
I'M
Possible
Ankit Kumar Avasthi
BUY NOW FROM
APNI PATHSHALA APP.
पहले 7 दिन की बुकिंग पर बुक बिलकुल फ्री

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
ECONOMY
POLITY
HISTORY
GEOGRPHY
1500X4
₹ 6000/-
₹4500/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

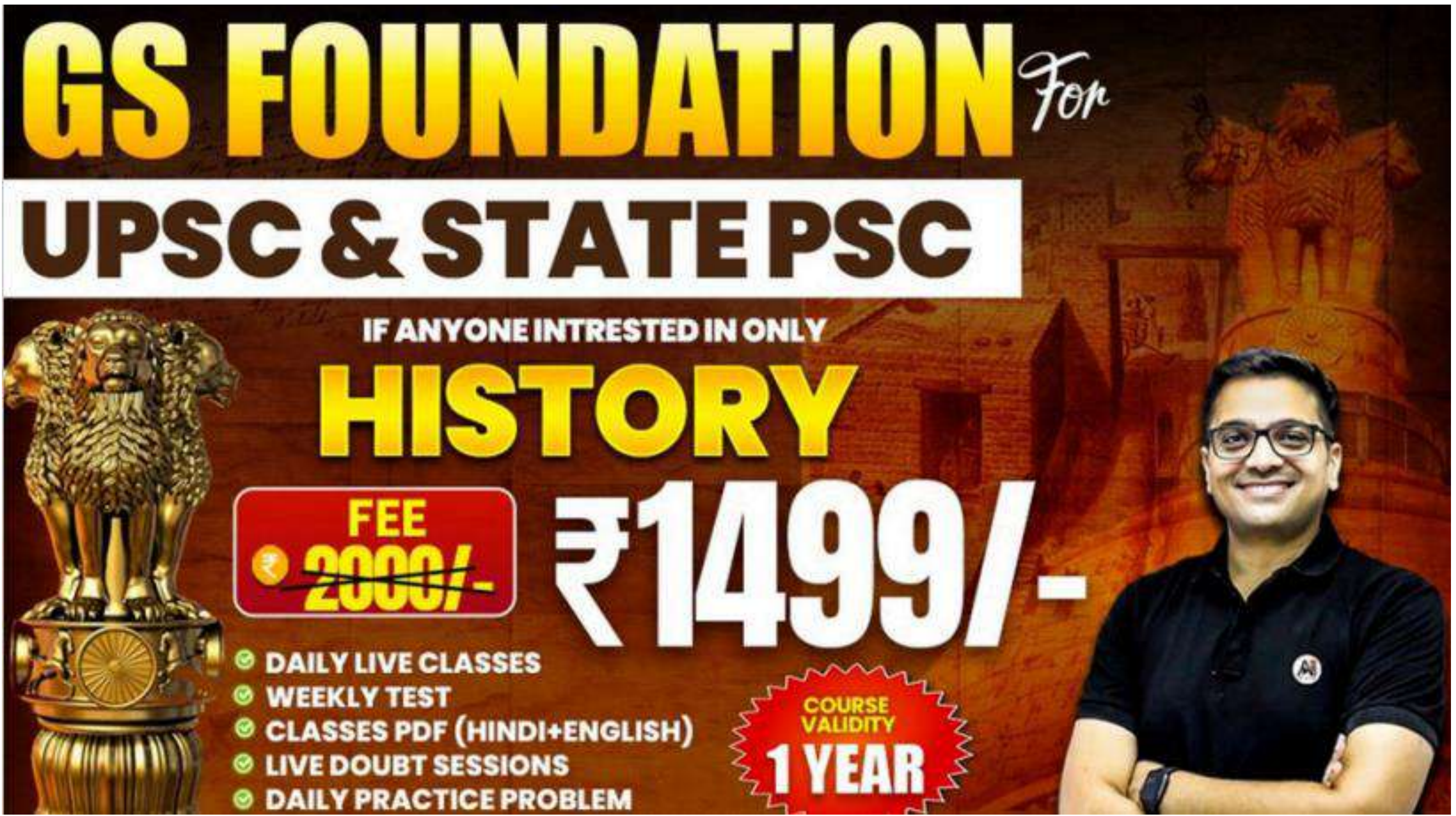

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
HISTORY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
ECONOMY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

जानिए
भारतीय संविधान
CONSTITUTION
OF
INDIA
मात्र
1499/-Year
Enroll Now !
1 year validity

GS FOUNDATION
Hand Written Notes
BEST OFFER
1999Rs
4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Bilingual
By Ankit Avasthi Sir

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण
RNA : Real News Analysis
MONTHLY CURRENT AFFAIRS
UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
MONTH
जनवरी, 2025
By Ankit Avasthi Sir
MONTHLY MAGAZINE
FREE!
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Billingual
ANKIT AVASTHI SIR

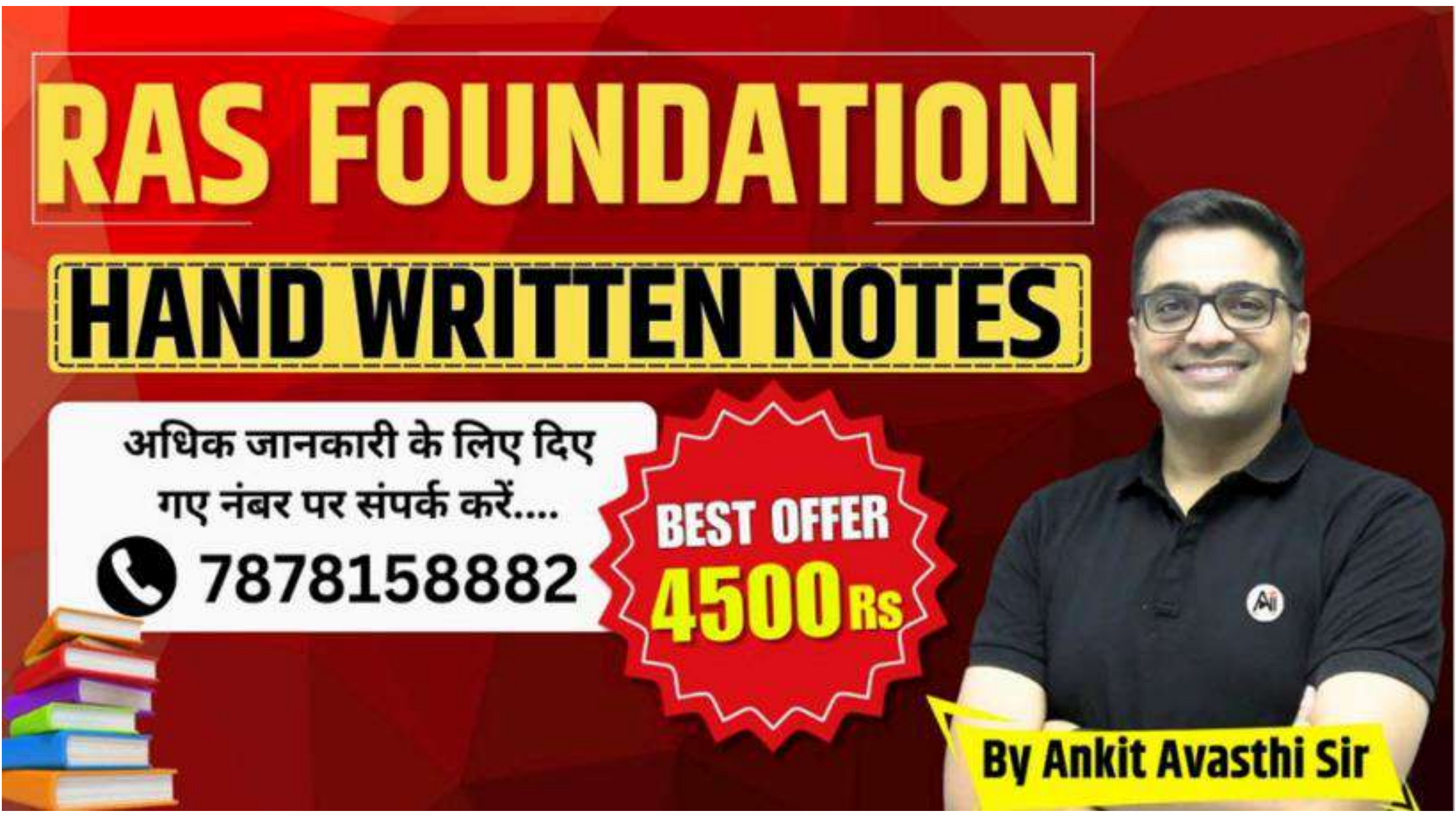
RAS FOUNDATION
HAND WRITTEN NOTES
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
BEST OFFER
4500 Rs
By Ankit Avasthi Sir

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
BBK
Baaten Bazaar ki
COUPON CODE
ANKIT500
Course fee
₹1999/-
Course fee
₹1499/-
Special
OFFER ON
Father's
DAY
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुआत

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
COUPON CODE
ANKIT500
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
Course fee
₹1499/-
Special
OFFER ON
Father's
DAY
एक निवेश समझदारी से..
Course Validity
1 YEAR

नई संस्करण
Pathshala
भूगोल-I
भूगोल-II
इतिहास-I
इतिहास-II
अर्थव्यवस्था
भारतीय राजव्यवस्था
जनरल साइंस & टेक्नोलॉजी
जी.ए फाउंडेशन
हैंडरिटन नोट्स
लॉन्च हो चुके हैं..
अभी खरीदें -
1999/-
(नियम और शर्तें लागू)
और पाएं साइंस की बुक फ्री (7 दिन तक)

CALL
CENTRE
HOW MAY I HELP YOU
7878158882
AnkitInspiresIndia
Download "Apni Pathshsla" app now!
Follow us: